सोमवार को रवींद्र भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन करते मंत्री भीम सिंह, नीतीश मिश्रा। साथ में प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, अमिताभ वर्मा और अन्य।

जनता के साथ सरल व्यवहार करें बीडीओ

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

भीम सिंह बोले

- पंचायत सचिवों को समरूप तरीके से कार्य का बंटवारा करें
- प्रखंड विकास पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला
- बीडीओ की उनके प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा होगी : नीतीश मिश्रा

राज्य में विकास दर कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जनता के बीच यह इम्प्रेशन बन रहा है कि अफसरशाही हावी होती जा रही है। इस धारणा को ठीक करना जरूरी है। इसके लिए कार्य रूप आपको तय करना है। ये बातें पंचायती राज मंत्री डॉ. भीम सिंह ने कही। वह रविन्द्र भवन में एक दिवसीय प्रखंड विकास पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार जनता के बीच इम्प्रेशन से चलती है। ठीक से व्यवहार करना बीडीओ का दायित्व है। विधायकों और ग्रामीण स्तर पर मौजूद जन प्रतिनिधियों से अक्सर यह शिकायत मिलती है कि बीडीओ ठीक से व्यवहार नहीं करते, मान-सम्मान नहीं करते और किसी आयोजन की सूचना नहीं देते। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये शिकायतें गलत हों, लेकिन अगर इनमें थोड़ी भी सच्चाई है तो इसे सुधारने की आवश्यकता है।

मंत्री ने कहा कि भविष्य में बीडीओ कार्यालय का नाम बदलकर पंचायत समिति कार्यालय किया जाएगा। राज्य में पंचायत सचिवों के 3100 पद खाली हैं। पंचायत सचिवों को समरूप तरीके से कार्य का बंटवारा करें। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के पीछे सरकार का मकसद शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना है। लोकतंत्र में मंत्रियों या जनप्रतिनिधियों के लिए डिग्री नहीं होती है। प्रधान सचिव समेत तमाम अधिकारियों का दायित्व जनप्रतिनिधियों की सहायता करना है। उन्होंने कहा कि बीडीओ जनप्रतिनिधियों के साथ सरल व्यवहार करें। जन प्रतिनिधियों को सप्ताह में दो दिन गाड़ी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। परंतु इसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। कई जिलों में जनप्रतिनिधियों को मानदेय की राशि समय पर नहीं मिलती है। प्रमुखों की शिकायत होती है कि बीडीओ उन्हें अपना चैम्बर नहीं देते हैं। इन्हें दूर करने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों के बीच सरकार की छवि कैसे सुधरे, इसका ध्यान बीडीओ को रखना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि सभी बीडीओ की उनके प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा होगी। जिनका प्रदर्शन खराब होगा, उनपर कार्रवाई होगी। एक स्थान पर तीन वर्ष पूरा करने वालों का तबादला किया जाएगा। बीडीओ का प्रदर्शन सुधारने के लिए उनका प्रशिक्षण समय-समय पर बिपार्ट और हैदराबाद में कराया गया है।

पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ वर्मा ने कहा कि पहले चरण में 1435 पंचायत सरकार भवन बनने हैं। इसमें 1190 का स्थल चयन कर लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था को 2800 करोड़ मिलने जा रहा है। इन्हें शत-प्रतिशत खर्च करने की बड़ी जिम्मेवारी बीडीओ पर होगी। स्वागत भाषण ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन जीविका के सीईओ अरविन्द कुमार ने किया।